

संपादकीय

सख्ती के साथ...शिक्षा भी

जनतांत्र जनगणना की मांग के बीच महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर विचार करने का एक और कोण भी चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील व राज्य सभा संसद कपिल सिंहल का सवाल लाजिमी है। कठोर कानून बन जाने मात्र से क्या समस्या का समाधान होना अथवा किया जाना संभव है? उन्होंने कहा सख्त कानून से ज्यादा जरूरी है, महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोलना। घरेलू दिसा पूरी तरह से नहीं रुकी है। बहुत सारे मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। सिंहल का विचार सकारात्मक है। जब तक महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को द्वारा नहीं सुनिए समस्या के समाधान को सही दिशा नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां यदि खेतों में काम कर रही हीं तो शिक्षा केसे होती है?

कोलकाता के आरजी का अस्पताल में हुए दुष्क्रम-हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 'अपराजिता बिल' पारित किया जाना क्या लाभदायक होगा? समाज जब तक स्वयं आगे नहीं आता, कानून क्या होगा? यहां प्रताड़ना का शिकायत ही है, वे समाज से ही आती हैं और समाज के ही लोग अपराधों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वज्ञत है कि छोटी जातियों, दलितों तथा गरीबों को ही सर्वाधिक तकलीफ झेलना पड़ती है। 'दिल से विद कपिल सिंहल' शीर्षक साक्षात्कार के इद-गिर्द भी समस्या को देखते जाने की जरूरत है। सिंहल ने शिक्षा को बेहतर, अवश्वक बताया। पितृसमक्त सोच और जनता व्यवस्था के दारों में समस्या को देखना जरूरी है। सामाजिक तौर पर इस प्रकार के 'कॉकल' को देखा जाना चाहिए, जिसके पीछे जातियों विचार भी महत्वपूर्ण है। दरअसल, इस अपराध में शिकायत ही महिलाओं को देखना जाना चाहिए, जिसके पीछे जातियों के इद-गिर्द भी समस्या को देखते जाने की जरूरत है। सिंहल ने अधिकारी और समाज के ही लोग अपराधों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वज्ञत है कि छोटी जातियों, दलितों तथा गरीबों को ही सर्वाधिक तकलीफ झेलना पड़ती है।

और अंत में

फेसबुक पर रविवार देर शाम प्रियंका गांधी वाडा की एक पोस्ट गोरखलब है। लिखा-लूट के मामले में गैरकान्ती तरीके से निरोप को ही फंसाने की कोशिश पिछले दिनों यूपी में रायबरेली के एक जनसुविधा केन्द्र पर कोई गई थी। कानून का राज है या राजनीतिक सरक्षण?

